There will be no 'Question Hour' on these days. There will also be no Private Members' Business on Friday, the 31st July, 1998.

The Committee also allotted time for Government Legislative Business as follows:—

	Business	Time Allotted
1.	Consideration and return of the Beedi Workers' Welfare Cess (Amendment) Bill, 1998, as passed by Lok Sabha.	1 hour
2.	Consideration and passing of the following Bills after they have been passed by Lok Sabha:—	
	(a) The Interest on Delayed Payments to Small-scale and Ancillary Industrial Undertakings (Amendment) Bill, 1998.	2 hours
	(b) The Oil fields (Regulation and Development) Amendment Bill, 1998.	2 hours
	(c) The Export-Import Bank of India (Amendment) Bill, 1998.	2 hours
	(d) The Cotton Ginning and Pressing Factories (Repeal) Bill, 1998.	1 hour

RE. DEMAND FOR DISCUSSION ON GOVT's DECISION TO PRIVATISE THE PUBLIC SECTOR

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Ghulam Nabi Azad, please.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Sir, I have a submission to make on the Business.

MR. CHAIRMAN: Mr. Azad, please wait. He has something to say on the Business.

SHRI JIBON ROY: Sir, my submission is this. We are discussing so many things here. But there is one important thing for which we have not found time. This is in regard to the Government's decision to privatise almost the entire public sector. Seventy-five per cent is to be disinvested. I had raised this issue in the House sometime back. My colleagues had also raised it. Sir, is it that the public sector workers, numbering twelve lakh, have no right to be heard? The public sector is going to be privatised, without this issue being discussed in the House. I submit to you, I had raised this issue earlier also. I requested you to look into this matter. If this is the position, where would the workers' voice be heard? Does it mean that Parliament has nothing to do with the labour? I submit this for your consideration, Sir.

MR. CHAIRMAN, Now Shri GHULAM NABI AZAD, please.

RE-KILLINGS BY MILITANTS IN DODA

श्री गुलाम नबी आज़ाद (जम्मू और कश्मीर): माननीय सभापति जी, पिछले तीन चार महीनों से जम्मू और कश्मीर में और विशेष रूप से सुबह जम्मू के डिस्ट्रिक्ट डोडा में आतंकवाद से जो परिस्थिति बन रही है, उस पर बहुत गहरी चिन्ता हम प्रकट करते हैं। मुझे

अफसोस से कहना पड़ता है कि इसी साल अप्रैल में पहली दफा सुबह जम्मू में उधमपुर में 17 अप्रैल को पठानकोट में 26 हिन्दू मारे गए मिलिटेंट्स के द्वारा और मैं समझता हूं कि जम्मू और काश्मीर में यह पहला वाक्या होगा कि इतनी ज्यादा संख्या में एक ही जगह पर, एक गांव में मिलिटेंट्स के द्वारा इतने लोग मारे गए हों। पूरा देश और यह सदन और दूसरे सदन ने भी इस पर अपनी चिन्ता प्रकट की थी। माननीय गृह मंत्री जी वहां गए थे, सीनियर आफिसर्ज़ गए थे, हमारी पार्टी की अध्यक्ष मिसेज सोनिया गांधी भी गई थीं, बहुत सारे लोग हम में से वहां गए थे लेकिन मुझे अफसोस है कि इसके बाद भी कोई खास कार्यवाही नहीं की गई। इसी तरह से इसी साल की 18 जून को ऊधमपुर के पास में ही जहां से उधमपुर खत्म होता है और डिस्ट्रिक्ट डोडा शुरू होता है, चापनारी में एक दूसरा वाकया हुआ जिसमें 25 बारातियों को मारा गया, दिनदहाड़े मारा गया, दिन के डेढ़ बजे मारा गया। क्या कभी ऐसा हुआ था कि दिन के डेढ़ बजे 25 लोग मारे गए हों। 23 जून को उसी एक हफ्ते के अन्दर माननीय गृह मंत्री जी वहां गए, सीनियर आफिसर्ज़ गए और उन्होंने उनके साथ बातचीत की और 24 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी ने श्रीनगर में वहां के गवर्नर, वहां के मुख्य मंत्री, सीनियर सिविल आफिसर्ज़ आर्मी और सिक्युरिटी फोर्सिज़ के साथ मीटिंग की।

उस 24 तारीख के हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में आडवाणी साहब की मीटिंग की वहां से रिपोर्टिंग होती है—

"Advani Announces Four-pronged Plan to Check Militancy."

इंडियन एक्सप्रेस लिखता है—

"'Anti-militancy Pro-development' are Advani's new J.K. Buzz Words. Advani Owns Responsibility for Massacre."

सर, यह 24 तारीख की बात हुई। उसके बाद 29 तारीख, सिर्फ 4 दिन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मीटिंग बुलायी। 26 या 27 के बीच में यह तय हुआ कि एक हाई पावर वर्किंग कमेटी का डेलीगेशन माननीय प्रधान मंत्री से मिले। 29 तारीख को डा० मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 7 वर्किंग कमेटी के मेम्बर्स का डेलीगेशन, जिसमें मैं भी था, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय होम मिनिस्टर साहब से, प्रधान मंत्री जी के घर पर मिला और हमने जम्मू-काश्मीर तथा विशेष रूप से सूबा जम्मू में और डिस्ट्रिक्ट डोडा में बढ़ते हुए आतंकवाद पर अपनी पार्टी के तरफ से, देश की तरफ से जम्मू-काश्मीर के लोगों की तरफ से, जम्मू के लोगों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों की तरफ से चिंता प्रकट की और माननीय प्रधान मंत्री और होम मिनिस्टर से निवेदन किया कि इस पर कुछ न कुछ कार्यवाही की जाए।

उसके बाद कल वह वाकया हुआ। कल के वाकये में फिर ठाकराई किश्तवाड़ में 16 आदमी मारे गए। पेपरों ने लिखा है 80-85। वह जिगजैग है। पहाड़ में नीचे से जाएं तो बहुत दूर लगता है। यह वह इलाका है जहां 1977 में मैंने विधान सभा का इलेक्शन लड़ा था और इस इलाके को, उस ठाकराई को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। यह किश्तवाड़ जो सब-डिवीजन, हेड-क्वार्टर है, वहां से पगडंडी से डेढ़ किलोमीटर मेन सिटी से है। घूम घुमाकर शायद 25-30 किलोमीटर होगा। वहां कल के दिन फिर 16 आदमी मारे गए।

माननीय सभापति जी, जैसा मैंने अर्ज किया कि पहले गृह मंत्री जी गए, ऊधमपुर भी गए, चापनारी भी गए चापनारी में गृह मंत्री जी ने बताया था कि आज के बा कोई वाकया नहीं होगा। लेकिन एक्जैक्टली उसके एक महीने के बाद यह वाकया हुआ। 17 से 23 जुलाई तक इसी महीने 4-5 रोज पहले तक मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट डोडा का दौरा किया। डोडा, भदेरवाह, किश्तवाड़-जहां यह वाकया हुआ, तकरीबन जैसा मैंने कहा कि किश्तवोड़ से अगर आप पगडंडी से जाएं तो एक-डेढ़ किलोमीटर है-वहां मैं रूका। अपने दौरे के दौरान इन तीनों, चारों के तहसील हैडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स में मैंने खुद सिविल आफिसर्स से, डिप्टी-कमिश्नर से, एस०डी०एम० से, एस०एस०पी० से एडीशनल एस०पी० से और जो दूसरे सेंट्रल पैरा-मिलिट्री के साथी हैं उनसे बातचीत की। उनकी एक ही मांग थी कि हमारी वीपनरी को मजबूत किया जाए, हमारे फोर्सेज को स्ट्रेन्थन किया जाए। यह बात मैंने 24 तारीख की दोपहर को माननीय गृह मंत्री जी को भी पार्लियामेंट के इनके चैम्बर में बतायी। वहां के लोगों की चिंता और डिस्ट्रिक्ट डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन की चिंता और जो मैंने उनसे चर्चा की थी, वह सब मैंने गृह मंत्री जी के सामने रखी थी। मैंने उनसे निवेदन किया था कि वहां फोर्सेज को स्ट्रेन्थन एस०किया जाए।

1995-96 में जब पूरा दबाव मिलिटेंसी का काश्मीर घाटी में था उस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमारी फोर्सेज डबल थी। आज जबकि दबाव पूरे सूबा जम्मू और डिस्ट्रिक्ट डोडा में है तो वहां सेंट्रल फोर्सेज की प्रेजेंस आधी है, 1995-96 के मुकाबले में। लिहाजा मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है?

यह खुशकिसमती की बात है कि आज गृह मंत्री जी जो स्वयं काश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टिर भी हैं, यहां हैं वरना हम जीरो आवर में यहां खुद ही सुनते हैं और खुद ही बोलते हैं। उस पर कोई एक्शन नहीं होता है।

इन तमाम बातों को नजर में रखते हुए मैं माननीय गृह मंत्री जी से तीन चीजें पूछना चाहता हूं। 23 जून को आप काश्मीर गए थे जब पहला वाकया हुआ था डिस्ट्रिक्ट डोडा में और 24 तारीख को आपने सिविल और सीनियर आफिसर्स से वहां मीटिंग की थी....। और जिसमें आपने एनाउंस किया था, 'आडवाणी एनाउंसेज़ फोर प्रोंग्ड प्लान टू चैक मिलिटेंसी,' तो यह 'फोर प्रोंग्ड प्लान' का क्या हुआ? उसके बाद उसमें फॉलो-अप कहां तक हुआ? दूसरा जो 29 जून को वर्किंग कमेटी का डेलीगेशन माननीय होम मिनिस्टर और माननीय प्रधान मंत्री जी से मिला जिसमें हमने निवेदन किया था कि इसमें कोई कार्यवाही करें, इसके एक महीने आगे, एग्ज़ैक्टली 29 जुलाई आज है, एक महीने में क्या फालो अप हुआ पी०एम० हाउस से या गृह मंत्रालय से फोर्सेस को स्टैथन करने के लिए, मिलिटेंसी को कम करने के लिए, कंटेन करने के लिए और वी०डी०सी० विलेज डिफेंस कमेटीज़ जिनको हथियार दिए गए थे, लेकिन वे हथियार ओब्सोलीट हैं, 303 जिस पर कि मैं आज से 30 साल पहले स्कूल में और कालेज में एन०सी०सी० की ट्रेनिंग करता था, वही 303 आज मिलिटेंट्स के साथ लड़ाई करने के लिए दी जाती है और खास तौर से विलेज डिफेंस कमेटीज़ को, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा मज़ाक कोई हो नहीं सकता, जो कि इस बारे में उन्होंने किया और परसों आज से एक हफ्ता पहले माननीय गृह मंत्री जी से वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो चिंता प्रकट की थी उसके बारे में गृह मंत्रालय से क्या कार्यवाही की गई?

माननीय सभापति जी, आज जो कोलंबो में शिखर सम्मेलन चल रहा है और हमारे प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री नवाज़ शरीफ से बातचीत करने वाले हैं, मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा अवसर है, इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट डोडा और जम्मू-कश्मीर के लोगों और अपनी पार्टी तथा मेरे ख्याल में दूसरे सदन के साथियों को भी इसमें कोई आब्जैक्शन नहीं होगा, इस सदन के द्वारा, आपके द्वारा माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह मैसेज पहुंचना चाहिए कि यह सदन और देश जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंट्स का मुकाबला करने के लिए और सख्ती से मुकाबला करने के लिए उनके पीछे है, उनके साथ है। हम कभी भी उसमें पीछे नहीं रहेंगे। जहां तक देश के हित का, देश की एकता का, देश की अखंडता का और देश की स्वतंत्रता को कायम रखने का संबंध है, कांग्रेस हमेशा किसी भी सरकार की सहायता करेगी, मदद करेगी। लेकिन हम सरकार से भी यह अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह भी आगे बढ़े। लेकिन एक कान से सुने और दूसरे कान से अगर निकाल दे तो खाली मदद करने से कोई फायदा नहीं होता। आज हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से साफ-साफ बात करें कि मीटिंगें तो होती रहती हैं, फोरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर होती हैं, फोरेन सेक्रेटरीज़ के लेवल पर मीटिंग होती है, पिछले 7-8 वर्षों से यह मीटिंगों का सिलसिला तो जारी रहा है और कभी-कभी प्रधान मंत्रियों की मीटिंगें भी दूसरे देशों में होती रहीं, चाहे पहले वाले प्रधान मंत्री हों या आज के प्रधान मंत्री हों, लेकिन जम्मू-कश्मीर में मिलिटेंसी में कोई फर्क नहीं आया है। मिलिटेंसी बढ़ती गई है। अगर पाकिस्तान एक तरफ से कहता है, हम बात-चीत करते हैं तो तकरीबन जब तक कोई हल नहीं निकलता है, जब तक वह बात-चीत किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती है, तब तक तो कम से कम मिलिटेंसी बंद हो। लेकिन एक तरफ से वे लोगों को मारें भी, एक तरफ से अपने मिलिटेंट भी भेजें, एक तरफ से फोरेन मर्सेनरीज़ भी भेजें, एक तरफ से अपने पुराने सिपाही भी भेजें जो पाकिस्तान में आर्मी में हैं और हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को मारें और दूसरी तरफ से वह बात-चीत का रास्ता भी खुला रखे, तो मैं नहीं समझता कि ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं। हां, अगर कोई परपज़फुल बात-चीत हो तो हम उसका हमेशा वेलकम करते हैं। लिहाज़ इस सदन के द्वारा मेरे ख्याल में प्रधान मंत्री जी को मैसेज जाना चाहिए कि इस दफा इस शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ ठोक बजा कर इस देश की तरफ से बात करें और मिलिटेंसी का खात्मा करने के लिए हमारी बात उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली): सभापति महोदय, गुलाम नबी आजाद जी ने जो प्रश्न उठाया है, उस बात पर यह सारा सदन और सारा देश अपनी चिंता प्रकट करता है।

सभापति महोदय, कल जो घटना हुई, उस से सारे देश की आत्मा हिल गयी है। सारे देश का मन कांप उठा है। यह घटनाएं पिछले कई सालों से घट रही हैं और यह आतंकवाद पिछले 9-10 वर्षों में हजारों लोगों की बलि ले चुका है। कल 5 व्यक्ति अपहृत किए गए।

महोदय, अपहृत व्यक्तियों की मौत जिन हालत में होती है, उसे देखकर मानवता की कांप जाती है। जब उन की लाशें मिलती है तो उन के कलेजे निकाल लिए होते हैं, उन के कई अंग काट लिए होते हैं, उन की आंखें निकाली होती हैं, उन के गले धीरे-धीरे रेतकर उन्हें मारा होता है या उन को पानी में डुबो-डुबोकर मारा होता है। महोदय, लोग घरों में बैठे टी०वी० देख रहे हों, कुछ लोग आएं और बच्चे, नौजवान व महिलाओं की हत्या कर दें, यह ऐसे लोमहर्षक कृत्य हैं जिन पर कि पशु को भी शर्मिंदा होना चाहिए। परंतु जो बात गुलाम नबी जी ने कही, वह बात बिल्कुल साफ है कि इन घटनाओं में आई०एस०आई० का हाथ बिल्कुल साफ हो जाता है। इन आतंकवाद की घटनाओं से जाहिर है कि पाकिस्तान एक तरह की प्रोक्सी वार लड़ रहा है। महोदय, आप पाकिस्तान टी०वी० को देखें तो वहां हिन्दुस्तान के खिलाफ युद्ध का उन्माद खड़ा किया जाता है और इन घटनाओं को इस तरह से जस्टीफाई का हनन किया जाता है कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। महोदय, कश्मीर में जिस तरह से मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा है, अगर उसे ठीक ढंग से दुनिया के सामने लाया जाए तो उस से सारी दुनिया को हिल जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब पाकिस्तान के साथ बात हो रही है तो जैसा कि गुलाम नबी जी ने कहा सारा देश प्रधान मंत्री के पीछे है कि इस संबंध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बात होनी चाहिए और जहां हम आपस में संबंध सुधारने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान काश्मीर में इस आतंकवाद को और प्रोक्सी वार को समाप्त करे। महोदय, जेहाद के नाम पर वहां भाड़े पर कई दूसरे देशों के लोग इस दुष्कृत्य में शामिल है। वहां कई भाड़े के सैनिक पकड़े गए हैं, उन की डायरियां पकड़ी गयी हैं और उन से सबूत पकड़े गए हैं जिन से उन घटनाओं के पीछे आई०एस०आई० का हाथ पूरी तरह से साफ हो जाता है। महोदय, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के समय इस सवाल को भी उन के सामने रखा जाए कि किस तरह से वहां बेचारे और बेकसूर लोगों की नृशंस हत्याएं की जा रही हैं।

महोदय, इस बारे में फारूख अब्दुल्ला जी के जो वक्तव्य आए हैं और उन्होंने प्रधान मंत्री जी से जो बातें कही हैं और जिस तरह से काश्मीर के अंदर उन को परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ रहा है, सभी राजनीतिक दलों के लोग मारे जा रहे हैं, उन संबंध में उन्होंने कई सुझाव आप के सामने रखे हैं। महोदय, यह बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वहां लोगों को स्वचालित हथियार दे दिए जाएं तो लोग खुद भी इन का मुकाबला कर सकते हैं। इन संबंध में एक योजना भी बनायी गयी है जिस के संबंध मे गृहमंत्री जी बताएंगे कि उन की योजना क्या है? परंतु मैं यह जरूर चाहता हूं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है और गृह मंत्री जी ने खुद भी कहा था कि उन मरे हुए लोगों को देखकर उन का दिल दहल गया है। मैं चाहूंगा कि उन सब की वीडियों रिकॉर्डिंग तैयार की जाए और सारी दुनिया को दिखाई जाए कि पाकिस्तान किस तरह से उन नृशंस हत्याओं में शामिल है और सारी दुनिया के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के इस दुष्कृत्य को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराने के लिए प्रयास किए जाए। महोदय, मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी जब वापिस आएंगे तो उन की पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से आतंकवाद के बारे में क्या बातें हुई, उन्हें वह सदन के सामने रखेंगे। महोदय, गुलाम नबी आजाद जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि दोनों सदन और सारा देश इस संबंध में प्रधान मंत्री जी के पीछे है और हम चाहते हैं कि वह पाकिस्तान से इस संबंध में दो टूक बात करें।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Chairman, I associate myself with the submission made by Shri Ghulam Nabi Azadji and Prof. Vijay Kumar Malhotraji.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Mr. Chairman, Sir, this is an issue—cutting across party lines—on which the entire country should condemn these brutal killings. This is an occasion for us to expose Pakistan in international fora about their subvertive activities that are being indulged in by them from time to time. In the last 20 years, more than 18,000 people were killed in Kashmir. In these killings Pakistan's hand is known to everybody. In the recent days, some of the militants were killed. The mercenaries were identified as people from Pakistan, people from Sudan, people from Afghanistan. These people are being imparted training. They are being given arms and ammunition. They are doing it with a purpose. The purpose is to subvert India, to weaken us and to cripple us econmically. This is a grand design of such countries who are inimical to India. They want to weaken our system. They want to subvert our

country. That being the case, we should now take strong steps. I totally agree with Shri Ghulam Nabi Azadji.

I had been to Jammu and Kashmir recently. I met not only my party workers but also other sections of the public. I got their opinions. Everybody is very agitated, very, very worried. Everyone wants additional forces to be sent to those places, particularly, Dada, Rajouri and Poonch.

Secondly, the Village Defence Committees should be strengthened further. Sophisticated arms should be given to the Village Defence Committees so that they will be able to encounter the militants as and when they attack them.

Another disturbing fact has come to my notice. As you all know, in Punjab, when militancy was at its peak, it was the local police aided by the Indian paramilitary forces that tackled the militancy there. Unfortunately, in Kashmir, the information is that certain elements which are not friendly towards us have also infiltrated into the administration and the police force. This is really disturbing. Unless those people are identified and weeded out of the administration, the local people there who are helpless and always depend on the State administration or the Central Administration, will not be able to fight effectively. Even the Chief Minister and the other leaders have to be guarded by the Central forces. That shows the situation there. The local administration also includes such people who are not willing to fight against the militants. This is one important thing which the Government of India, particularly the Union Home Ministry, should take note of and take steps to weed out such elements from those sensitive positions.

Thirdly, talks are now going on in the SAARC today. This occasion should be utilised by the Government of India and the Prime Minister to convey to Pakistan, in no uncertain terms, that the entire country is agitated, that we are strongly condemning the happenings. Pakistan should be told, "Hands off India. We really want good neighbourly relationship with you and we want you to be strong, stable and prosperous; but, at the same time, please do not interfere in India's internal affairs, we will not tolerate this." In this language, it has to be communicated to Pakistan. That is my request. Thank you.

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): आदरणीय सभापति महोदय, एक बहुत बुरी घटना कल कश्मीर के डोडा जिले में हुई है, जिसके लिए हम बहुत चिंतित हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी पहली घटना नहीं हुई है। अभी तक कश्मीर घाटी में और डोडा जिले में हमारे हजारों भाइयों को इन हत्यारों द्वारा मारा जा चुका है। हम उस विषय पर यहां चिंता व्यक्त करते हैं और आगे ऐसा न हो, इस बारे में हम कदम उठाएंगे, ऐसी चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के कांड रुक नहीं रहे हैं। तो मेरा कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं रुकतीं, इस बारे में भी हमें थोड़ा सतर्क होकर देखना पड़ेगा। जैसा अभी बताया गया मानवाधिकार के बारे में, इस विषय पर दुनिया हमें समझाने की कोशिश करती है कि हम कैसे बर्ताव करें, अमरीका हमको समझाने की कोशिश करता है और हमारे जवान वहां जब आंतकवादियों पर कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टैप्स उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर मानवाधिकार आयोग के माध्यम से दबाव डालने की कोशिश की जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं जैसा अभी प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा जी ने भी कहा, कि गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी इस विषय पर ऐसी कुछ योजना बनाएं जिससे कि वे जो अत्याचार वहां पर कर रहे हैं, वे अत्याचार सब जगहों पर मीडियों के माध्यम से पहुंचें, वीडियो के माध्यम से दिखाए जाएं और लोग समझें कि आंतकवादी वहां पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और इन्हें यदि बंद करना है तो उनके ऊपर भी मसल पॉवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा।

मसल पावर का इस्तेमाल उनके विरुद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उसमें किसी को रुकावट डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब उस मसल पावर का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी कुछ हो सकेगा। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अभी कश्मीर में हमारे जवानों ने आंतकवादियों के पास से कुछ हथियार पकड़े हैं और हथियार पकड़े गए हैं, उनकी प्रदर्शनी यहां

लगी हुई थी और उसकी डिटेल्स यहां उपलब्ध हैं। यह सब देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हथियार बरामद किए गए, वे हथियार 2 डिवीजनों के लिए पर्याप्त थे। मतलब यह कि 11,000 अधिकारियों और जवानों के लिए वे हथियार पर्याप्त थे। इतने वैपंस और एम्युनिशन उनके पास से बरामद किए गए हैं। हम सरकार को बार-बार इस बारे में बताते हैं। आज आडवाणी जी गृह मंत्री हैं, पहले जब दूसरे गृह मंत्री थे, तब भी हमने बताया था और हम हर समय इन्हें बचाते थे कि उनको आई०एस०आई० का सपोर्ट है और इसके सबूत ऐनेक्सी में लगी प्रदर्शनी में देखे जा सकते थे। यह सब होने के बाद भी हम एक्रॉस दि टेबल चर्चा कर रहे हैं कि आप ये रोको-रोको।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आडवाणी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी श्रीलंका गए हुए हैं। वे वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलकर बात करने वाले हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि आप उनको साफ-साफ बता दीजिए कि यह सब रोकने की इच्छा है या नहीं? आप उनके सामने सबूत रखकर बात करो कि यह सब आपके यहां से हो रहा है। आप इसे बंद करने वाले हो या नहीं? अगर बंद नहीं करने वाले हो तो उसके लिए हमें क्या कार्यवाही करनी पड़ेगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है और उसी ढंग से कदम उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि यह कभी बंद हो सकेगा। इसके लिए उसी ढंग से उनके विरुद्ध हथियार लेकर हमें खड़ा होना पड़ेगा।

महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब करने के बाद यदि हमारे वहां रहने वाले भाई लोग हाथ में सोफैस्टिकेटेड हथियार लेकर सामने खड़े होते हैं और हमारी पुलिस के हाथ में 303 हो तो काम नहीं बनेगा। उन लोगों के हाथ में हथियार है, वही हथियार हमारे लोगों के हाथ में भी होना चाहिए। जब इस ढंग से उनको जवाब दिया जाएगा, तभी यह बंद होगा नहीं तो यह बंद होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सरकार को सतर्क होकर इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश इस विषय में आपके साथ होगा, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

SHRI E. BALANANDAN (Kerala): Sir, this is a serious question we are now discussing. Everyone in the House is worried about it. Since the Home Minister is here, I want to inform him about the massacres that had been taking place since April, 1998. The first massacre took place at Udhampur on April 26 in which 26 people had been killed and the second massacre took place at Doda on June 25 in which another 25 persons had been killed. Yesterday, this distressing incident took place. I want to know exactly what steps the Government is taking to see that the life of the people is protected and their confidence is restored. If it goes on this way, then the people will totally lose their confidence. I want the Home Minister to come and tell us—he is here luckily what steps he has taken from April 26 onwards till date and what protection is being given to the people. I want to have a statement from the Home Minister so that we all are educated. We will in one voice protest against this kind of cruelty being committed against unarmed citizens. This is the fate of the people. The Home Minister should see to it that all types of protective measures are taken to guard the life of people in Kashmir Valley.

प्रो० रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, श्री गुलाम नबी आजाद साहब ने जो मामला उठाया है उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि निरन्तर यह घटनाएं एक इलाके में हो रही हैं। हम लोग जानते हैं कि स्थानीय पुलिस होती है उसको इस तरह के अपराध करने वालों की जानकारी भी होती है वह कहां रहते हैं, हाईडआउट्स क्या हैं, उनकी भी जानकारी होती है। ऐसा लगता है कि हमारे जो बी०एस०एफ० के और आर्मी के लोग हैं उनको सही सूचना स्थानीय पुलिस के द्वारा नहीं दी जा रही है, वरना कोई वजह नहीं कि तमाम पुलिस बल के रहने के बावजूद, पैरा मिलिट्री फोर्सेज के रहने के बावजूद इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो। एक तो मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी इस बात को भी जानने की कोशिश करें कि क्या हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेज को, आर्मी के लोगों को स्थानीय पुलिस का सही सहयोग मिल पा रहा है? अगर ऐसा होता तो कोई वजह नहीं कि यह लोग ऐसी घटनाएं बार-बार कर सकें। दूसरे, बहुत दिनों से मामला पड़ा हुआ है। हमारी पंजाब और राजस्थान की सीमा पर जब तार की बाड़ लगी तो उधर से आने वाले लोग बंद हो गए। लेकिन जो काश्मीर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है उस पर हमारा मेटीरियल पड़ा हुआ है, सारा सामान पड़ा हुआ है लेकिन वह बाड़

नहीं लग पा रही है। अगर हिन्दुतान की गवर्नमेंट पूरी इच्छा शक्ति के साथ कि जब रोज लोग मारे ही जा रहे हैं और यह बढ़ता ही जाएगा और सारी दुनियां जानती है कि पाकिस्तान सरकार के इशारे पर है। आई०एस०आई० वगैरह छोड़िए-आई०एस०आई० क्या है, it is the Pakistani Government. पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। अगर यह नहीं रुकेगा तो अंतिम परिणति युद्ध के रूप में होगी दोनों देशों की। तो वह स्थिति आए हमें सख्ती से कम से कम जो हमारा एक प्लान है उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई उधर से इधर न आ सके, सीमा पर जो तारों की बाड़ लगाने का इरादा है उसमें मजबूती से अमल करना चाहिए, मैं माननीय गृह मंत्री से मांग करना चाहता हूं।

SHRI S.R. BOMMAI (Karnakata): Sir, I associate myself with the sentiments that have been expressed by the hon. Members here. This is a vexed problem which we have been facing during the last decade. It is absolutely necessary to give protection to the prople of Kashmir, particularly of Jammu and Doda districts, and to see that no repetition of such acts takes place. I appreciate the sincerity and the promptness with which the Home Minister had acted. After the incident he personally visited there. If there is any plan, if it can be disclosed to the House, the House can be informed about the details. If you want to keep it as a secret and act, we welcome that also. But no repetition of such incidents should take place. Keeping that Border Security Force, the paramilitay forces and the Army on alert is not sufficient. We have to take the people of Kashmir into confidence. They are divided. A section of the people are colluding with the terrorist forces and part of the administration is also colluding with the terrorist forces. This should be eradicated. Otherwise, it is very difficult to control such incidents. Sir, I visited Kashmir myself as party President and as Minister. I met the people. We have to create a climate of confidence and convince this section of the people who are colluding with the anti-national forces and Pakistani forces.

Open a dialogue with them. How it should be done and when it should be done, it is for the Government to decide. I would like to make one more suggestion. Let us start a people-to-people contact between Pakistan and India. Non-official delegations, intellectuals, lawyers, doctors, etc. should intensify people-to-people contact so that an opinion can be built up in Pakistan (*Interruptions*). I am saying that there should be a people-to-people contact between Pakistan and India. People-to-people contact is a must. Public opinion should be built up in Pakistan so that it can influence the Government of Pakistan.

Let the Prime Minister take a firm stand. We are all with him so far as this issue is concerned.

Thank you.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, two days back I had been to Jammu. I had an occasion to have a discussion with some political leaders of that area. They said that the people living in that area are always living in terror and horror. They also said that those persons, who were in a position to go to some other place, vacated that area and went to a safer place; whereas those persons, who could not afford to leave that place or who were constrained to live there with their little holdings, were living there is terror.

Yesterday, in the massacre which took place in Doda, they killed 23 persons. I think it is not politically motivated. It is just a 'tit for tat'. They are playing with the lives of the people. If asked, "Why, was the situation in the border areas like this?" They said Pakistan wants that the political climate should be in their favour so that they can use this situation as a leverage for their political advantage. That is the situation there. The innocent persons of India should not be made victims. Our Prime Minister, when he meet the Prime Minister of Pakistan in Colombo, should say in clear terms that India will not tolerate this kind of torture

and terror emanating from Pakistan. I would request the Government to take effective steps to see that the life of the poor people living in that area is safe.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद सभापति महोदय। काश्मीर में जो जघन्य घटनाओं के द्वारा समूह का समूह आए दिन कत्ले-आम किया जा रहा है, इसकी मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से घोर निन्दा करता हूं। महोदय, घटनाओं के पुनरावृत्ति में बार-बार ये बातें आती है कि आई०एस०आई० का हाथ है। यहां विदेशी आपराधिक एजेंसियों के द्वारा घटनाएं कराई जा रही हैं, यह बहुत ही निन्दा की बात है किंतु मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जब आई०एस०आई० के लोग सक्रिय रूप से आपराधिक घटनाओं को करते हैं और घटना हो जाने के बाद हमारी खुफिया एजेंसी को यह एल०आई०ओ० या सी०आई०डी० या सी०बी०आई० के लोगों को पता चलता है कि आई०एस०आई० का हाथ है या किसी आपराधिक संगठन का हाथ है तो यह हमारी एल०आई०ओ० और जो खुफिया एजेंसी हमारे देश की है, यह क्यों नहीं इस घटना का पहले ही पता लगा लेती है? घटना होने से पूर्व ही क्यों नहीं पता लगा लेती है कि इसमें आई०एस०आई० का हाथ है या किसी भी आपराधिक संगठन का हाथ है, तो उसकी पूर्व-योजना को ही विफल कर दे? हमारे देश की खुफिया ऐजेंसी अगर इसका पता लगा ले और पूर्व नियोजित आपराधिक कार्यों को विफल कर दे तो मेरी समझ में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और मैं समझता हूं कि यह हमारी कमजोरी का परिचायक है कि सही समय पर सही आपराधिक घटनाओं का पता लगाने में हमारे देश की खुफिया ऐजेंसी पूरी तरह से विफल है। इसी के कारण अपराधों में लगतार वृद्धि हो रही है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे देश की खुफिया ऐजेंसी को मजबूत एवं सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किए जाएं एवं हमारी ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए, वह उन्हें उपलब्ध कराए जाएं ताकि इन अपराधों की पुनरावृत्ति न हो सके।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA (Uttar Pradesh): Sir, while associating myself with the views expressed by Shri Ghulam Nabi Azad, I want to share with the House, through you, and with the hon. Home Minister my experiences in Punjab.

Sir, it is clear from such incidents that people across the border have a clear strategy, a one-point programme, that is, the programme to destabilise the country, and the strategy is to create chaos in India. Innocent people have always been made victims of such people and soft-targets are attacked. I don't share with the view or I don't support the view of the hon. Member that our intelligence agencies have failed. They have not failed. They are doing their duty well. In Punjab also, there was such a situation. I don't want to refer to those unfortunate incidents here. Some people said that one community was responsible for it. It is wrong. In Punjab, the success started only when information from common man started pouring into enforcing agencies, law and order maintenance agencies. I only urge upon the Home Minister that he must find out why the co-operation of the common man is not available in Kashmir. Then, I would like to know what the reasons are as to why information from common man is not available to the enforcing agencies, the law and order maintenance agencies. Some measures must be adopted and steps must be taken to see to it that information started coming in. It is only because of this that there was success in Punjab. And I am sure that we will succeed in kashmir as well. So, I associate myself with the views expressed by Mr. Ghulam Nabi Azad.

श्री खान गुफरान जाहिदी (उत्तरप्रदेश): चेयरमैन साहब, मैं अपने आपको इस संगीन मसले के साथ, जिसको गुलाम नबी आज़ाद साहब ने और हमारे दूसरे मौजूद मैम्बरान ने उठाया है, अपने को संबद्ध करते हुए 2—4 बातें कहना चाहता हूं, जनाब-ए-आली, कश्मीर में आम हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं, इन वाक्यात के बाद जो तस्वीरें सामने आती है, वहां की मुस्लिम औरतों को रोते हुए देखा गया है, तकलीफ से तड़पते हुए देखा गया है, मकसद यह है कि इसी वक्त जब कि हमारे मुल्क के प्रधान मंत्री अटल जी वहां मिल रहे हैं, उस मुल्क के नवाज़ शरीफ साहब वहां आ रहे हैं; हमारे वज़ीर-ए-आज़म से वह मिल रहे हैं, ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान ने, जिसने प्रॉक्सी वार

वहां शुरू कर रखी है, वह इस तरह की मीटिंग का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। एक तरफ नारा-ए-अमन भी है, दूसरी तरफ जंग की तैयारी भी। वह अमन की बात भी करना चाहते हैं और जंग के लिए भी इस तरह की प्रॉक्सी वार करने की कोशिश करते हैं। इसका एक सियासी मकसद है। इस दहशतगर्दी के पीछे एक सियासी मकसद है और वह यह है कि इस दहशतगर्दी के जरिए से दो कौमी नजरियों को हिन्दू-मुस्लिम के बीच के निफाक पैदा करना, पाकिस्तान-हिन्दुस्तान की आम जनता के बीच में एक फर्क डालना, एक ऐसी फिजा पूरे मुल्क में क्रिएट करना ताकि तशदुद फूट पड़े, कयास हो जाए, फिरकावाराना बुनियादों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए। हमारे देश में संगीन हालात पैदा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से मुसलसल इस तरह के तरीके अपनाएं जा रहे हैं।

डोडा में और उसके आसपास वाकियात जिस तरह से गुजर रहे है उससे जह जाहिर होता है कि वाकई हमारी आर्मी इंटेलीजेंस और पुलिस इंटेलीजेंस जो है वह पूरी तरह से फेल हो गई है। हमें तो अफसोस यह होता है कि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने अप्रैल के बाद वहां पर जो एलानात किए और आप एक-दो बार वहां पर गए और आपने कहा कि हम इस तरह का चारनुकाती एक फैसला दे रहे हैं, एक एक्शन प्लान दे रहे हैं, मैं तो यह समझता हूं कि इस तरह के वाकियात अगर अब भी हो रहे हैं तो वह एक्शन प्लान फेल हो गया है और उसकी कोई हैसियत अब नहीं रह गई है, वह पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। सच्ची बात यह है कि वह वजीर आला, जो उस रियासत का है क्योंकि यह कांक्रीट सब्जेक्ट है अगर वह अपने मुल्क की, अपने इलाके की अक्लियतों की हिफाजत नहीं कर सकता है तो अच्छा होता अगर फारूख अबदुल्ला साहब इस्तीफा दे देते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार अगर इस तरह के वाकयात मुसलसल होते हैं तो अक्लियतों की हिफाजत में वह नाकाम हो गए हैं इसीलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी तरह से हम समझते हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने अगर वहां पर यह फैसला लिया था, मैं जज्बात में यह बात नहीं कहा रहा हूं बेहतर इकदामात नहीं हुए और यह सिलसिला फिर दुबारा हुआ तो उनको इसके बारे में अफसोस का इजहार करना चाहिए और आइन्दा ऐसी इकदामात करना चाहिए, इस्तीफा तो उनको भी देना चाहिए अगर वह नाकामी महसूस करते हैं। लेकिन अगर वह ऐसा महसूस करते हैं कि नहीं, हमने किया लेकिन हुआ नहीं तो उसके लिए फिर उनको ऐसे इकदामात करने चाहिए जिससे काम हो। साथ ही साथ सारा मुल्क आज यह चाहता है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के वजीर-ए-आजम जो आपस में मिल रहे हैं वह जंग से नहीं अमन में बैठकर के अपनी बातों को तय करें और एक अच्छे फैसले पर पहुंचें ताकि इस तरह के वाकियात जो काश्मीर में हो रहे हैं और इन्सानियत का कत्लेआम हो रहा है, दर्दनाक सुरतेहाल है। इन्सानों का कत्ल हो रहा है, हम सब के दिल जज्बात से भरे हुए हैं, हमें बे-पनहा अफसोस है, उसका इज़हार करना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि वह कामयाब हों। अगर कामयाबी नहीं होती है तो पाकिस्तान में जहां कि दहशतगर्द उगते हैं और आते हैं और यह जज्बात यहां फैलाए जाते हैं उसके खात्मे के लिए कोई मुस्तकिल प्लान बनाना चाहिए ताकि इस तरह से पाकिस्तान हमारे घर में आ कर, दाखिल हो कर हमारे मामलात को खराब न करे। मैं इन अल्फाज के साथ अपने आपको दूसरे साथियों के जज़बात से संबद्ध करता हूं।

श्री गया सिंह (बिहार): माननीय सभापति जी, मैं गुलाम नबी आजाद जी का समर्थन करते हुए गृह मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पूरा हाउस आपके साथ है और आपकी सरकार आने से जम्मू-काश्मीर के लोगों को उत्साह हुआ था और उनके अन्दर यह भावना बनी थी, कई अखबारों में यह चर्चा हुई कि पटेल साहब के बाद आडवाणी जी होम मिनिस्टर बने हैं, अब यह तो लोहा हैं, कुछ करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप फेल हो चुके हैं और आपने जितने जोर से इस हाउस में पीछे कहा था जब ऐसी घटना हुई थी तो लोगों को लगा था कि कुछ कार्य योजना आपकी ऐसी है जिससे अब काश्मीर में दुबारा ऐसी घटना नहीं होगी। कल जो घटना हुई है उसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम है। उसकी पूरा देश निन्दा करने के लिए तैयार है और कर रहा है लेकिन गृह मंत्री जी को महसूस करना चाहिए और हाउस के सामने कहना चाहिए कि आपने जो वायदा किया वह कहां पर फेलियोर है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपकी आर्मी की इंटेलीजेंस है, आपकी बार्डर सेक्योरिटी फोर्स है उसका अपना इंटेलीजेंस है और जैसा आपने कहा था कि दुबारा घटना होने के पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। परन्तु आपकी ये एजेन्सियां फेल्योर हुई हैं। यह पहाड़ में है और सिटी से बहुत नजदीक है। यह घटना एक गांव में नहीं हुई है। एक गांव में तो घर से निकालकर उनको मारा, उसके बाद फिर दूसरे गांव में भी जाकर मारा और इसमें काफी

समय लगा। इस प्रकार आपकी एजेंसीज फेल हुई हैं। इसलिए हाउस के सामने आपको यह कबूल करना चाहिए और यह वायदा करना चाहिए... हाउस आपके साथ है, देश आपके साथ है आपके जो करामात में वह कब निकलेंगे, चार महीने का समय हो गया और काश्मीर में लोग मर रहे हैं। लोगों ने कहा था कि यह सरकार बनी है, अब हम अपने घर लौटेंगे। आपने भी कहा था कि उनको घर लौटायेंगे। अब घर लौटने के बजाए पुनः वहां से लोग भागना शुरू करेंगे। यह बहुत दुखद चीज है, दुखद घटना है। हम समझते हैं कि होम मिनिस्टर को इसको गम्भीरता से लेते हुए हाउस को कांफीडेंस में लीजिए, देश को कांफीडेंस में लीजिए और हम लोगों को यह बताये कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर नहीं होंगी।

DR. KARAN SINGH (Jammu and Kashmir): Sir, having represented the Udhampur constituency in the Lok Sabha for 18 years, I fully support the line taken by my friend and colleague Shri Ghulam Nabi Azad in expressing deep pain, anguish and sorrow at what is happening there. Sir, the people living in that area are simple patriotic folks. They are now living under a cloud of terror. The terror is palpable. They cannot sleep at nights. One never knows when and where the next strike is going to be. Let me point out one clarification. My dear friend Margabandu talked about the border. Doda is nowhere near the border. Doda is 300 kilometres from the border. I think the House should realise that it is not a border incident. Quite evidently these people have come in in an organised manner. They are living within the State and then they are able to strike. It is not a hit and run situation at all. It means very clearly, that these groups of highly armed and highly motivated militants are residents in those areas and can, therefore, choose the place and time at which they want to strike. I think, the House should be aware of the gravity of the situation. The situation is that we have been unable to deal with people who have been living in the area under our control now for several years. The first thing, of course, to do is to try and stop the ingress. The question arises, how do they get in? Why can we not do something more effective to stop the ingress?

The second question that arises is that once they are in and once they are operating there — I think, it is generally known in which areas they are operating—why are we unable to do anything about it? Sir, I would suggest on thing. I do not want to go into the broader problems and question related to Jammu and Kashmir, on some other occasion we can do that. The Prime Ministers are meeting today in Sri Lanka. One can only hope that something positive will come out of it. But, immediately whatever may be the result of the SAARC Summit, we have to gear ourselves up in such a way that there is a rapid reaction. My view is that in areas that are sensitive, for example, in Kistwar, in Bhadrwah, in Doda, in Ramban and in Gulgulabgarh, there should be rapid reaction forces immediately available. They should be available on telegraph so that they can react immediately and some specific action can be taken.

Sir, 20 years ago, we made a suggestion, and Ghulam Nabi will remember, that a cantonment should be costructed at Bhadrwah. The land was also acquired. For some odd reasons which I cannot understand, no steps were taken to construct that cantonment in Bhadrwah.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Land has been acquired for that purpose.

DR. KARAN SINGH: The land has been acquired. I know, I was there. I know every inch of that area like he does. Why was that not taken up? If you have had a proper cantonment in Bhadrwah by now, you would have been able to have a much better reaction.

Secondly, Sir, I must say I have just come back from Leh yesterday. Our Armed Forces are doing a magnificent work.

But, there seems to be a definite plan to activate the entire line of control. there has been shelling in Kargil over the last

one or two days; there have been some casualties. In the Kargil town, shells have landed in the town and the whole atmosphere is sought to be disturbed. We have to have a proper liaison between the Defence forces, the paramilitary forces, the State administration, the police, and the local citizens. This is lacking. I must say regretfully that there is no proper co-ordination between all these forces as a result of which nobody is taking the responsibility. First of all, I would express on behalf of all of us our deep anguish. Can you imagine, Sir bridgegrooms going to be married being massacred along with the *barat* on the way? What greater crime can there be against humanity? Is this the way to further a religious cause or a political cause? So, we express our deep sympathy, and I hope that effective steps will be taken. It is no use saying that you will never allow another incident to take place.

1.00 P.M.

I am afraid even if you do say that, I would not take it at its face value because as long as you have those people operating there, they can strike at any time and at a point of their choice. But, what I would like to know from the Government is: How is that these people are operating there almost without any check? Why is it so that we cannot do something effective about it?

मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी (उत्तर प्रदेश): चेयरमैन साहब, जनाब नबी आजाद के जरिए जो मसला उठाया गया है मैं उससे अपने को वाबिस्ता करते हुए हिन्दुस्तान के और इंसानियत के दुश्मनों को अपनी पार्लियामेंट और अपने ऐवान से यह कहना चाहता हूं कि:

"हिन्दू का कत्ल है न मुसलमां का कत्ल है,
ए दुश्मनाने हिन्द यह ईसा का कत्ल है।"

इस प्रकार की वारदातें रोजमर्रा मामूल बन गई है। बहुत बातें हमारे साथियों ने कह दी हैं। मैं उन तमाम लोगों को खिराजे अकीदात पेश करता हूं जो जुल्म के शिकार हुए हैं और अपने फर्ज से कोताही करने वाले या फराएज को न पहचानने वाले लोगों से यह कहना चाहता हूं कि मुल्क की आजादी की रखवाली इस तरह से की जा सकती है जिस तरह से मुल्क को आजाद करवाने के लिए लोगों ने दारें रसन का पुंदा चूमा था। जितनी कुर्बानियां मुल्क को आजाद करवाने के लिए दी गई हैं, उससे ज्यादा कुर्बानियों की जरूरत आन पड़ी है, मुल्क की आजादी और खुदमुख्तारी की हिफाजत के लिए हम में से सारी पार्टियों के लोग, इस सोगवार घटना के लिए अपने उन मजलूम, दुनिया से जाने वाले लोगों का शोक मना रहे हैं और दरिन्दों की मज्जमत कर रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बार्डर पर सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है। पाकिस्तान से आने वाले ये आतंकवादी आसमान से तो नहीं टपकते हैं। जाहिर है कि ये जमीन से चलकर आते हैं और अगर हम भारत की सरहदों की हिफाजत की कसम खाते हैं तो हमारी कसम कहां टूट रही है, हम पर यह सवालिया निशान लगे बगैर नहीं रह सकता। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता हं, लेकिन में किसी पर उंगली न उठाते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा कि पुलिस का काम है कि शहरों में फौज या पैरा-मिलिटरी फोर्सेस को आतंकवाद के बारे में खबरदार करना। खुफिया एजेंसी का यह काम है, उसे यह जरूर करना चाहिए और में समझता हूं कि वह इसे जरूर कर रहे होंगे। मगर बार्डर पर जो फोर्स लगी हुई है, जिस बार्डर से हमारे दुश्मन मुल्क में दाखिल हो रहे हैं तो आखिर बार्डर पर वे कौन से काम में लगे हुए हैं जिसकी वजह से दुश्मन हमारे मुल्क में दाखिल होने में कामयाब हो रहा है? दुश्मन यहां आकर नफरत का माहौल पैदा कर रहा है और चाहता है कि सारे बार्डर पर नफरत का माहौल पैदा हो, कश्मीर में नफरत का माहौल पैदा हो। हिन्दुस्तान के किसी भी इलाके में नफरत का माहौल पैदा होगा तो तास्सुब की घटायें उठेंगी और खून का पानी बरसेगा। इस नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए जरूरी काम मुसस्सल पुरानी गवर्नमेंट में भी होते रहे और यह गवर्नमेंट भी करने की ख्वाहिश रखती है और आज दोनों प्रधानमंत्री श्रीलंका में इकट्ठे हो रहे हैं। श्रीलंका में दोनों प्रधानमंत्री इकट्ठे हो रहे हैं चूंकि जो दोनों जगह आवाम परेशान हैं, यहां की आवाम भी परेशान है, पाकिस्तान की अवाम भी परेशान है। इंसानों में मजलूमियत जो सर उभार रही है, जुल्म के जरिए, इस बारे में कहना चाहता हूं कि सिर्फ बातचीत तक ही यह सारा मामला फिर मुझे लगता है, कि महदूद रह जाएगा। मैं नहीं समझता कि हुकूमत के अंदर कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसा फैसला करने का मूड है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को दो-दो-चार में बात समझाई जा सके। पाकिस्तान केवल बातों के जरिए

समझने वाला नहीं है। पाकिस्तान मसलेहत के जरिए समझने वाला नहीं है। पाकिस्तान खुशअखलाकी और खुशकिरदारी के जरिए समझने वाला नहीं है। पाकिस्तान के साथ ताकत की जुबान से आपको बात करनी होगी। अगर आप ताकत की जुबान में बात नहीं करेंगे तो हम यकीन के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि "मरीजे इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की"। मैं नहीं समझता कि इस तरह से कंट्रोल हो जाएगा और ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि कल भी हमें शोक मनाना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से बयान देने के बावजूद हम जिस तरह से लाचार हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, बेकस हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं।

इस मजबूरी में एक तरफ हम न्युक्लियर बम का धमाका कर रहे हैं और दूसरी तरफ दुश्मन ने हमें चूहा और बिल्ली समझ लिया है। जब दुश्मन चाहता है तब हमें ललकार देता है, जब दुश्मन चाहता है हमारी सरहदों पर हमला करता है। 11-12 साल से यह जो सर्द जंग हो रही है इसमें मालूम नहीं कितने हिन्दुस्तानियों का खून पानी की तरह सस्ता करके बहवा दिया गया है। मैं आपसे नहीं कहता कि आप जंग कीजिए मगर आप बिल पावर के ज़रिए, आप अपनी ताकत के ज़रिए, आपकी नेगोसियेशन में, आपकी बोली में गोली से ज्यादा ताकत होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पर आपका दुश्मन सहम कर झुकने के लिए मजबूर हो। मानवता को ललकारा जाना, हिन्दुस्तान के लोगों को इस तरह से बेआबरू करना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। सारी दुनियां में हिन्दुस्तान अमन का हामी रहा है। अभी अभी गुफरान ज़ाहिदी साहब कह रहे थे कि एक तरफ नज़रिया-ए-अमन की बात हो रही है दूसरी तरफ जंग का रास्ता पैदा किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नज़रिया-ए-अमन तो हमारे पास है और अखबारे-ए-जंग पाकिस्तान के पास है। वह तो पेपर में भी अगर मुफ्तगु करते हैं तो जंग की ज़बान में जंग नाम रख कर करते हैं। सर, जहां तक हिन्दुस्तान और जम्मू और कश्मीर के तहफुजो वकार का सवाल है मैं अपने ख्यालात का इज़हार इन अल्फाज़ में करना चाहूंगा कि गैरों को मये गंगोजमन दे नहीं सकते। अगर पाकिस्तान यह चाहता है कि कश्मीर को हड़प कर लेगा, अगर हिन्दुस्तान में अफरातफरी पैदा कर के हिन्दुस्तान को मुतज़लज़ल और गैर मुस्तहकिम कर देगा तो हम तमाम पार्टियों के लोगों को पार्टी से ऊपर उठ कर पाकिस्तान के इस नापाक ख्वाब को किसी भी कीमत पर शर्मिंदा-ए-ताबीर नहीं होने देना चाहिए और हर हाल में उसको कह देना चाहिए कि गैरों को मय गंगोजमन दे नहीं सकते। हम दुश्मन को गंगा जमना का पानी नहीं देंगे।

> गैरों को मये गंगोज़मन दे नहीं सकते,
> हम अहले वतन खाके वतन दे नहीं सकते,
> कश्मीर बड़ी चीज़ है क्या देंगे किसी को, हम देश
> के दुश्मन को कफन दे नहीं सकते।

इसलिए हमें बड़ी ही मिन्नत और समाजत के साथ अपने हुक्मरानों से कहना है जो लोग आज हम फर्ज से सुबुकदोष होना चाहते हैं, हम मुकम्मलतौर पर आपके साथ हैं। हर कदम पर देश के तहफुज के लिए तन, मन और धन के साथ पूरा हाऊस, पूरा देश आपके साथ है मगर खुदा के लिए आप अपनी मर्दानगी दिखलाइये, आप मैदान में आइये। आप इस तरह की हिन्दुस्तान की तौहीन करने वालों की ज़बान को लगाम दीजिए और अगर मुल्क इसी तरह से टूटता रहा, आतंकवाद इसी तरह से बढ़ता रहा तो कल आने वाले दिनों में मुल्क के आवाम किसी भी हकूमत पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बात एक आई थी कि वहां के आवाम को हथियार दे दिये जाएं। मैं सहमत हूं इस बात से। मगर आवाम को हथियार देने से पहले उन्हें ट्रेनिंग भी देनी होगी। बिना ट्रेनिंग के आवाम क्या हथियार चलाएंगे? अगर आवाम को ही अपनी हिफाज़त करनी है तो पुलिस का हथियार किस काम का है? पुलिस से हथियार जब्त कर लीजिये और आवाम को हथियार दे दीजिए। फौज से हथियार छीन लीजिए और आवाम को हथियार दे दीजिए। पैरा सिक्युरिटी फोर्स से हथियार ले लीजिये और आवाम को हथियार दे दीजिये बार्डर सिक्युरिटी फोर्स से कह दीजिए कि घर जा कर बैठे और अवाम को कहिये कि अपने घरों से बार्डर पर जा कर बा हैसियत बार्डर सिक्युरिटी फोर्स का काम करें। यह क्या मज़ाक है? इतनी फौज किस लिए है? इतनी पुलिस किस लिए है? क्यों अवाम हाथों में बंदूक लेंगे? क्यों पब्लिक बंदूक लेकर दुश्मनों का मुकाबला करेगी? यह दिन उस वक्त आएगा जब हमारे पास फौज नहीं होगी, जब हमारे पास बार्डर सिक्युरिटी फोर्स नहीं होगी। आज हम इन मामलों में दुनिया की किसी भी ताकत से कमज़ोर नहीं हैं। आवाम अपनी ताकत के साथ, अपने दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी सलाहियत के साथ, अपनी काबिलियत के साथ, अपने तन-मन और धन के साथ इस फोर्स पर फक्र करते हुए उसके साथ होंगे। मगर हजूर मुझे अर्ज यह करनी है कि हकूमत को एक्टिव होना चाहिए। सिर्फ नारा लगाना, दावा करना

और दलील के नाम पर खोखले हो जाना, इससे मुल्क नहीं बच सकता है। सब लोगों की चिंता है, हम भी इस चिंता में आपके साथ शरीक हैं, आप आगे बढ़िये, मर्दानाधार फैसला कीजिए, इंशा अल्लाह हम कभी बुज़दिल आपको साबित नहीं होने देंगे। मुल्क पूरा आपके साथ रहेगा और मुल्क के वकार का सौदा किसी भी दुश्मन को करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। शुक्रिया।

†مولانا عبید اللہ خاں اعظمی (بہار):
چیئرمین صاحب، جناب غلام نبی آزاد کے ذریعہ جو مسئلہ اٹھایا گیا ہے میں اس سے اپنے آپکو وابستہ کرتے ہوئے ہندوستان کے اور انسانیت کے دشمنوں کو اپنی پارلیمنٹ اور اپنے ایوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ:

ہندو کا قتل ہے نہ مسلمان کا قتل ہے
اے دشمنان ہند یہ انسان کا قتل ہے

اس طرح کی واردات روز مرہ کا معمول بن گئی ہیں۔ جو باتیں ہمارے ساتھیوں نے کہہ دی ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو ظلم کے شکار ہوئے ہیں اور اپنے فرض سے کوتاہی کرنے والے یا فرائض کو نہ پہچاننے والے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی آزادی کی رکھوالی اس طرح سے کی جا سکتی ہے جس طرح سے ملک کو آزاد کرانے کے لئے لوگوں نے دار و رسن کا پھندا چوما تھا۔ جتنی قربانیاں ملک کو آزاد کرانے کے لئے دی گئی ہیں، اس سے زیادہ قربانیوں کی ضرورت آن پڑی ہے، ملک کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کیلئے۔ ہم میں سے ساری پارٹیوں کے لوگ، اس سوگوار گھڑی میں اپنے ان مظلوم، دنیا سے جانے والے لوگوں کا سوگ منا رہے ہیں اور درندوں کی مذمت کر رہے ہیں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بارڈر پر سیکورٹی فورس موجود ہے۔ پاکستان سے آنے والے یہ آتنکوادی آسمان سے تو نہیں ٹپکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ زمین سے چلکر آتے ہیں اور اگر ہم بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کی قسم کھاتے ہیں تو ہماری قسم کہاں ٹوٹ رہی ہے، ہم پر یہ سوالیہ نشان لگے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا ہوں، لیکن میں کسی پر انگلی نہ اٹھاتے ہوئے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پولیس کا کام ہے کہ شہروں میں فوج یا پیرا ملٹری فورسز کو آتنکواد کے بارے میں خبردار کرنا۔ خفیہ ایجنسی کا یہ کام ہے، اسے یہ ضرور کرنا چاہئے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے ضرور کر رہے ہوں گے۔ مگر بارڈر پر جو فورس لگی ہوئی ہے، جس بارڈر سے ہمارے دشمن ہمارے دیش میں داخل ہوتے ہیں تو آخر وہ بارڈر پر کیسے کام میں لگے ہوئے

†[ ]Transilteration in Arabic Script

پاکستان کیول باتوں کے ذریعہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان مصلحت کے ذریعہ سمجھنے والا نہیں ہے، پاکستان خوش اخلاقی اور خوش گفتاری کے ذریعہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ طاقت کی زبان سے آپکو بات کرنی ہوگی، اگر آپ طاقت کی زبان میں بات نہیں کریں گے تو ہم یقین کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں:

مریض عشق پر لعنت خدا کی
مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

میں سمجھتا کہ اس طرح سے کنٹرول ہو جائیگا ایسی حالت میں میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی ہمیں شوک منانا پڑ سکتا ہے۔ پردھان منتری جی کی طرف سے بیان دینے کے باوجود ہم جس طرح سے لاغر ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، اس مجبوری میں ایک طرف ہم نیوکلیئر بم کا مظاہرا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دشمن نے ہمیں چھوٹا اور بلی سمجھ لیا ہے۔ جب دشمن چاہتا ہے تب ہمیں للکار دیتا ہے، جب دشمن چاہتا ہے ہماری سرحدوں پر حملہ کر دیتا ہے۔

گیارہ بارہ سال سے یہ سرد جنگ ہو رہی ہے اس میں معلوم نہیں کتنے ہندوستانیوں

ہیں جس کی وجہ سے دشمن ہمارے ملک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ دشمن یہاں آکر نفرت کا ماحول پیدا کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ سارے بارڈر پر نفرت کا ماحول پیدا ہو، ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں نفرت کا ماحول پیدا ہوگا تو تعصب کی گھٹائیں اٹھیں گی اور خون کا پانی برسے گا۔ اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لئے ضروری کام مسلسل پرانی گورنمنٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں یہ گورنمنٹ بھی کرنے کی کوشش رکھتی ہے۔ اور آج دونوں ملک کے پردھان منتری سری لنکا میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سری لنکا میں دونوں پردھان منتری اکٹھے ہو رہے ہیں چونکہ جو دونوں جگہ کے عوام پریشان ہیں، یہاں کی عوام بھی پریشان ہے، پاکستان کی عوام بھی پریشان ہے۔ انسانوں میں مظلومیت جو سرا بھار رہی ہے، قلم کے ذریعہ، اس بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف بات چیت تک ہی یہ سارا معاملہ پھنسا لگتا ہے، کہ محدود رہ جائیگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے اندر کوئی ایسی پاور ہے، کوئی ایسی شکتی ہے یا کوئی ایسا فیصلہ کرنے کا موڈ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کو دو دو چار میں بات سمجھائی جا سکے۔

کا خون پانی کی طرح سستا کر کے بہا دیا
گیا ہے - میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ
جنگ کیجئے - مگر ول پاور کے ذریعہ، آپ
اپنی طاقت کے ذریعہ، آپ کی نگوسیشن
میں، آپ کی بولی میں گولی سے زیادہ
طاقت ہونی چاہئے - جس کی بنیاد پر اپنا
دشمن سہم کر جھکنے کے لئے مجبور ہو -
مانوتا کو لاچار اجانا ہندوستان کے لوگوں
کو اس طرح سے بے آبرو کرنا یہ کوئی اچھی
بات نہیں ہے، ساری دنیا میں ہندوستان
امن کا داعی رہا ہے - ابھی غفران زاہدی
صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک طرف نظریہ
امن کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف
جنگ کا راستہ پیدا کیا جا رہا ہے - میں
آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ نظریہ امن تو
ہمارے پاس ہے اور اخبار جنگ پاکستان
کے پاس ہے - وہ تو پیپر میں بھی گفتگو
کرتے ہیں تو جنگ کی زبان میں جنگ
نام لکھ کر کرتے ہیں -

سر، جہاں تک ہندوستان اور جموں
کشمیر کے تحفظ کا سوال ہے اور اس کے وقار
کا سوال ہے میں اپنے خیالات کا اظہار ان
الفاظ میں کرنا چاہوں گا کہ غیروں کو سے
گنگا و جمن دے نہیں سکتے اگر پاکستان
یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کو ہڑپ کر لے گا اگر
ہندوستان میں افراتفری پیدا کر کے ہندوستان
کو متزلزل اور غیر مستحکم کر دے گا تو
ہم تمام پارٹیوں کے لوگوں کو پارٹی سے
اوپر اٹھ کر پاکستان کے اس ناپاک خواب
کو کسی بھی قیمت پر شرمندۂ تعبیر نہیں
ہونے دینا چاہئے اور ہر حال میں اسکو
کہہ دینا چاہئے کہ "غیروں کو سے گنگا و جمن
دے نہیں سکتے" ہم دشمن کو گنگا جمنا
کا پانی دے نہیں دیں گے -

غیروں کو یہ گنگ و جمن دے نہیں سکتے
ہم اہل وطن خاک وطن دے نہیں سکتے
کشمیر بڑی چیز ہے کیا دیں گے کسی کو
ہم دیش کے دشمن کو کفن دے نہیں سکتے

اس لئے ہمیں بڑی منت اور سماجت کے
ساتھ اپنے حکمرانوں سے کہنا ہے جو لوگ آج
اس سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں ہم
مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہیں - ہر قدم
پر دیش کے تحفظ کے لئے تن من اور دھن
کے ساتھ پورا ہاؤس، پورا دیش آپ کے
ساتھ ہے - مگر خدا کے لئے آپ اپنی مردانگی
دکھائیے، آپ میدان میں آئیے آپ
ہندوستان کی توہین کرنے والے کی زبان
کو لگام دیجئے اور اگر ملک اسی طرح سے
کو سنبھالئے، اتنکواد اسی طرح سے بڑھتا
رہا تو ملک کے رہنے والے دنوں میں ملک کے عوام
کسی بھی حکومت پر بھروسہ کرنے کے لئے
تیار نہیں ہونگے - بات ایک آئی تھی کہ

وہاں کے عوام کو ہتھیار دے دیئے جائیں، میں سہمت ہوں اس بات سے، مگر عوام کو ہتھیار دینے سے پہلے ان کو ٹریننگ بھی دینی ہوگی، بغیر ٹریننگ کے عوام کیا ہتھیار چلا لیں گے؟ پھر اگر عوام کو ہی اپنی حفاظت کرنی ہے تو پولیس کا ہتھیار کس کام کا ہے؟ پولیس سے ہتھیار ضبط کر لیجئے، اور عوام کو ہتھیار دے دیجئے، فوج سے ہتھیار چھین لیجئے اور عوام کو ہتھیار دے دیجئے۔ پیرا ملیٹری فورس سے ہتھیار لے لیجئے اور عوام کو ہتھیار دے دیجئے۔ بارڈر سیکورٹی فورس سے کہہ دیجئے کہ گھر جا کر بیٹھیں اور عوام سے کہہ دیجئے اپنے گھروں سے بارڈر پر جا کر بحیثیت بارڈر سیکورٹی فورس کا کام کریں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اتنی فوج کس کے لئے ہے؟ اتنی پولیس کس لئے ہے؟ کیوں عوام ہاتھوں میں بندوق لیں گے۔ کیوں پبلک بندوق لیکر دشمنوں کا مقابلہ کریگی؟ یہ دن اس وقت آئیگا جب ہمارے پاس فوج نہیں ہوگی، جب ہمارے بارڈر سیکورٹی فورس نہیں ہوگی۔ آج ہم ان معاملوں میں دنیا کی کسی بھی طاقت سے کمزور نہیں ہیں۔ عوام اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ، اپنی قابلیت کے ساتھ، اپنے تن من اور دھن کے ساتھ اس فورس پر فخر کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہونگے۔ مگر حضور مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ حکومت کو ایکٹیو ہونا چاہیئے۔ صرف نعرہ لگانا، دعویٰ کرنا، دلیل کے نام پر کھوکھلے ہو جانا اس سے ملک نہیں بچایا جا سکتا ہے۔ سب لوگوں کو چنتا ہے ہم بھی اس چنتا میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ آگے بڑھیئے، مردانہ وار فیصلہ کیجئے، انشاء اللہ ہم بھی بزدل آپکو ثابت نہیں ہونے دینگے۔ ملک پورا آپکے ساتھ رہیگا اور ملک کے وقار کا سودا کسی بھی دشمن کو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ شکریہ۔ "ختم شد"

श्री जितेन्द्र प्रसाद (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं कि जो विचार गुलाम नबी आज़ाद जी ने और बहुत से माननीय सदस्यों ने व्यक्त किया। ....(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: It is already 1 o'clock. I think, today, we will continue and skip the lunch.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal) : Sir, what about the statement?

MR. CHAIRMAN: That will come. It is in the agenda.

श्री जितेन्द्र प्रसाद: मान्यवर, महीने भर में यह तीसरी दर्दनाक घटना घटित हुई है। यह बहुत ही एक गम्भीर चिंता का विषय है। मैं सिर्फ कुछ सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

यह कहना चाहूंगा कि यह भारत सरकार की, हमारे गृह मंत्रालय की एक बहुत बड़ी विफलता है कि बार-बार इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जब भी घटना घटित होती है हम सदन के अंदर आते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं कहना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि इन्होंने अनाउंस किया था कि फोर प्रांग्ड इनका एक्शन प्लान होगा। उस एक्शन प्लान के तहत क्या हुआ? क्यों वह विफल हुआ? क्या वह एक्शन प्लान गलत था यह मैं आज जानना चाहूंगा।

श्री नगर गृह मंत्री महोदय तशरीफ ले गए थे। वहां पर जून के महीने में 24 तारीख को referring to the close and cordial relations between the Central Government and the State Government, Mr. Advani said, "Never before, in the current phase of militancy has the relationship been so friendly." जब इनको पूरा कोआपरेशन स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा था तब भी एक लोकलाइज्ड एरिया के अंदर बार-बार इस तरह की घटनाओं का होना बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। किसी ने कहा इंटेलीजेंस का फेल्योर है। किसी ने कहा कि लोकल पापुलेशन की मदद नहीं ली गयी। मैं सिर्फ सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर एक छोटे से एरिया की सुरक्षा पूरी भारत सरकार की शक्ति नहीं कर सकती है तो इससे बड़ी विफलता इस सरकार की नहीं हो सकती है। मैं आज कहना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि ये आज सदन को आश्वस्त करें, सदन के द्वारा खास तौर से जम्मू-काश्मीर की जनता को आश्वस्त करें, देश की जनता को आश्वस्त करें कि अब इस घटना के बाद दुबारा इस प्रकार की घटना कभी नहीं घटित होगी।

समाचारपत्रों ने, मान्यवर, यह छापा है कि जहां पर यह घटना घटित हुई वहां पर विलेज डिफेंस कमेटी गठित नहीं हुई थी जबकि गृह मंत्री महोदय के यह स्पष्ट निर्देश थे। वहां एक पुलिस चेक पोस्ट जो थी वह भी विदड्रा कर ली गयी थी जबकि गृह मंत्री के स्पष्ट आदेश थे कि वहां चेक पोस्ट बनायी जाए।

मैं यह पालिसी और हाट परसूट पढ़ता रहा हूं, सुनता रहा हूं। प्रो-एक्टिव और रिएक्टिव पालिसी भी सुनता रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कौन-सी पालिसी अपनाने जा रहे हैं जिससे कि उस एरिया में लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें और आज जो हम आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान पर, आई०एस०आई० पर, जिस पर भी, जो भी शक्ति हो जो भी इस कारनामे में लिप्त हों क्या हम अपने देश की जनता को और खास तौर से उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित नहीं रख सकते। आज फिर दुबारा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री आज यहां आश्वासन दें कि आज के बाद से दुबारा इस तरह की घटना घटित नहीं होगी। हम हर कदम उठाएंगे और पूरी भारत सरकार यह जिम्मेदारी ले कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। धन्यवाद।

कुमारी निर्मला देशपांडेय (नाम-निर्देशित): सभापति महोदय, भाई गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा, उसके साथ वहां पर डोडा में जो हुआ, उसके लिए अफसोस प्रकट करते हुए मैं कहना चाहती हूं कि डोडा एक ऐसा जिला है जिसके गांव-गांव और शहर-शहर से हम लोगों का परिचय है। इसलिए कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहती हूं कि किसी भी हालत में ऐसी घटना को लेकर वहां पर उस जिले में जो भाईचारा है मुसलमानों के बीच में—हमेशा जिस भाईचारे को देखकर बहुत खुशी होती है — उस भाईचारे को बनाए रखने की तरफ ध्यान देना जरूरी है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहती हूं आपके द्वारा कि आज जब दोनों प्रधान मंत्री मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, उसी वक्त इस घटना का होना — क्या इसके पीछे कोई और संकेत नहीं है? क्या कोई ऐसी ताकतें हैं जो दोनों देशों के बीच में दोस्ती नहीं होने देना चाहती हैं और उन ताकतों के इशारों पर ऐसी घटनाएं होती हैं? इस पर भी हमें गौर करना चाहिए।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहती हूं सरकार और जनता दोनों को अलग करना चाहिए। पाकिस्तान की जनता हिन्दुस्तान के साथ दोस्ती चाहती है, भाईचारा चाहती है, इस बारे में हमें कोई शक-शुबहा नहीं है। हमारे वहां के सैकड़ों दोस्त हर जगह मीटिंग कर रहे हैं, जलूस निकाल रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं कि हिन्दुस्तान के साथ हमें अपने मसलों को बात-चीत से हल करना चाहिए। किसी भी हालत में लड़ाई नहीं होने देना चाहिए। "जंग नहीं, हमें अमन चाहिए" यह नारा चारों तरफ वहां कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कुएटा में गूंज रहा है। यह मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहती हूं। इसलिए इस वक्त जरूरत है कि दोनों मुल्कों के लोग, दोनों मुल्कों के दानिशवर, दोनों मुल्कों के कलाकार, दोनों मुल्कों के सोचने-समझने वाले लोग मिलें, बात-चीत करें और अपनी-अपनी सरकारों से कहें कि गलत कदम मत उठाएं। इसकी तरफ ध्यान देना मैं जरूरी समझती हूं। मैं आपके द्वारा इस सदन को बताना चाहती हूं कि हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि किसी

श्री हालत में दोनों मुल्क जंग की तरफ न जाए, जब कि दुनिया की कुछ ताकतें हमको लड़ाना चाहती हैं, बर्बाद करना चाहती हैं और हमारी तबाही को देख कर सिर्फ अपनी हकूमतें चलाना चाहती हैं। इससे हमें सावधान, सतर्क हो जाना चाहिए और दोनों मुल्कों के अवाम के मेल-जोल को, भाईचारे को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

महोदय, यह वक्त है कि जब भावनाओं में बह कर किसी भी तरह के गलत कदम की तरफ हम न जाएं। यह जमाना युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है, अहिंसा का है।

धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री कुलदीप नैयर।

SHRI KULDIP NAYYAR (Nominated): Chairman, Sir, this is a very serious matter. And I think we should ponder over it with all our equanimity and balance. I do not think that Pakistan is going to stop proxy war. Whenever I have gone there and talked to lots of people at various levels, I found them saying. *Though I do not think that that is a reply because if something is being done from here, they should also do that. That is neither here nor there. The point I am trying to make is that Kashmir in Pakistan...

SHRI GUHLAM NABI AZAD: I thinki this should not form part of the record.

MR. CHAIRMAN: Please .....(*Interruptions*)... What Mr. Ghulam Nabi Azad .... (*Interruptions*).

SHRI KULDIP NAYYAR: I just mentioneod the name. Did I say ....(*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Please sit down. कुलदीप नैयर जी एक मिनट बैठिए। ....(व्यवधान) देखिए, जैसा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा ....(व्यवधान)

SHRI GHULAM NABI AZAD: This should not form part of the record.

MR. CHAIRMAN: I agree.

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI KULDIP NAYYAR: I tried to bring here what they were saying there. If you do not want to hear ....(*Interruptions*)

श्री सभापतिः देखिए जैसा गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा जो सदन का माहौल है उस बात में जो वह बात कही है वह हटा दी जाएगी। ...(व्यवधान)

श्री कुलदीप नैयरः महोदय, मैंने सिर्फ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः देखिए अब आप उस बारे में मत कहिए।...(व्यवधान)

SHRI KULDIP NAYYAR: I tried to bring you what they are saying. Whether it is a propaganda, I just brought it to your notice. did I support it or anything like that?

MR. CHAIRMAN: It was not required.

श्री कुलदीप नैयरः आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए...(व्यवधान) इस तरह की बातों से तो बात बनेगी नहीं...(व्यवधान)

I cannot really help you because you are...(*Interruptions*)

SHRI SATISHCHANDRA SITARAM PRADHAN: We don't want to hear you. (*Interruptions*)

SHRI KULDIP NAYYAR: Mr. Chairman, Sir, I have a right to speak. If this is going to be the atmosphere, how can I speak? (*Interruptions*) What kind of allegations they are making? (*Interruptions*)

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): The solemn atmosphere has been badly disturbed by you. (*Interruptions*)

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI (Uttar Pradesh): You clearly said that you subscribe to the statement that it is the ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Those words have been deleted. Those words have been expunged. I agree with Shri Ghulam Nabi Azad. On this question, the whole atmosphere was different. There is

solidarity. The speeches made by many Members here have been very good, reflecting the unity of the country. This is happening for the first time, perhaps. But it is a very healthy sign. Therfore, please keep up that atmosphere. There should be impartiality. More than impartiality, unity is required.

SHRI GHULAM NABI AZAD: That is right, Sir.

SHRI KULDIP NAYYAR: Thank you, Mr. Chairman.

Now, what is Pakistan trying to do there? We have, more or less, eliminated militancy in the Valley. Despite eveything, they have not been able to create an atmosphere whereby they could create distance between the Hindus and the Muslims. In the Jammu Region, in the higher reaches, they are trying to communalise the situation. Not only that. Although militancy had been suppressed there, they are trying to build a base on this side.

Knowing all these things—I think, the hon. Home Minister knows it much better than me—what are we going to do for the future? Even though we do our best to stop these people at the border—which, probably, we are doing—still, there would be some kind of infiltration taking place. I think, these people who are coming to Doda are coming through Anantnag. This is my information. Maybe, I am wrong.

The point is, we have to, some day, take up this topic seriously, with not really the Government only, but also with the intellectuals in Pakistan, with the newspapermen in Pakistan. Without discussing this matter with them, we will not be able to stop this, whatever steps we take. We should take some steps. No doubt about it. My humble suggestion is that the human rights organisations from this side and the human rights organisaitons from that side could, probably, make some kind of a front. People from both sides could make some kind of a joint front and see what is happening. *(Interruptions)* This is a suggesiton I am making. Maybe, at the people level, we are doing. Now, Mr. Chairman, ...

MR. CHAIRMAN: Over? Shri Pranab Mukherjee.

SHRI KULDIP NAYYAR: Not over. *(Interruptions)* Sir, this is a very strange kind of thing. Either you give me permission, or, you don't give me permission. I am not speaking further.

MR. CHAIRMAN: No. no. *(Interruptions)* I thought you had completed. *(Interruptions)*

SHRI KULDIP NAYYAR: This is not fair. So, I am not speaking. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: All right. Mr. Pranab Mukherjee. *(Interruptions)*

SHRI KULDIP NAYYAR: I do not wish to say. But how can the Chairman be partial? *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Please don't say that. *(Interruptions)* I thought you had completed.

SHRI KULDIP NAYYAR: No, No. How can you give permission to others?

MR. CHAIRMAN: Now, if you have not completed, please complete.

SHRI KULDIP NAYYAR: I have not completed. Did you ask me 'have you completed?

MR. CHAIRMAN: Yes. I thought you had completed. Please complete.

SHRI KULDIP NAYYAR: What about the time taken by them? Ten minutes were taken away by interruptions and then you shut me up.

MR. CHAIRMAN: Kindly complete your speech now.

SHRI KULDIP NAYYAR: Sir, as I started saying, we are passing through a very critical period: not only in this country, but in Pakistan also. Pakistan, after acquiring the bomb, has adopted a war-like posture. Now, can we think of 'hot pursuit' today? It is not possible

because one thing would lead to another. What we have to do is this. Through talks at various levels, at the intellectual level, at the people level, as I said, at the level of the human rights organisations, which we are trying to do, maybe, we would be able to do something. I am not saying that it is going to be easy, because Kashmir still gives Pakistan its ethos. There is nothing else which holds them together. So, my request to the House is: please consider this as an issue which belongs to all of us, to the country. There may be some people who may differ with you on something. But that does not mean that when it comes to something serious, there is any kind of division in this country or in this House. We are all with you on this point. But the only thing is that your approach may be different from that of ours. That is all.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, while associating myself with the observations made by Mr. Ghulam Nabi Azad and many others, I most humble submit that we are anguished. If the problem would have been merely that of law and order, killing of some persons, the discussion would have taken place in a different context. The problem has more than one dimension. All of us are fully aware of the gravity of the situation becuase all these incidents of militant activities are backed by cross-border logistic support. International terrorism is going to be one of the gravest menaces to peace and security in the post cold-war era.

When we met you in your chamber, Sir, as we understand, the whole purpose was to express the concern of the House over the way the terrorist activities, militant activities, are being supported by some country, particularly when we have become the victim, to convey the sense of our concern in the context of the discussion which is taking place between the two Prime Ministers, at Colombo. Though the SAARC has nothing to do with bilateral issues, taking the opportunity of the presence of two Prime Ministers, when they are meeting there definitely, they are going to discuss about it. We wanted to strengthen the negotiating position of our Prime Minister by expressing our own concern over the ever increasing terrorist activities in this country. The Doda incident is a manifestation of that.

I do entirely agree with the observations made by many Members that we should not vitiate the atmosphere because the situation is really crucial. There may be interested parties who want to vitiate the situation more even when the talks are going on. I do not expect that there will be a very positive outcome of the talks; it may not happen. But, at the same time, we have no option but to initiate the talks, to have a dialogue and to have some sort of understanding so that we can live in peace in this whole sub-continent itself. Therefore, I am not going to make any observations on this issue.

Most respectfully, through you, I would submit to the Government. The Home Minister is present here. He will definitely give his own response. In what manner he will like to respond, it is for him to decide. But, please convey the sense of the House, the feelings of the Members who have participated in this debate, to the Prime Minister in Colombo, so that he can keep our concern at the back of his mind while he is having his talks and negotiations with his counterparts in Colombo. This is my most respectful submission, through you, Sir, to the Government.

MR. CHAIRMAN: I hope the Government will convey to the Prime Minister the unanimous concern and support of the House for his negotiations with the Prime Minister of Pakistan.

Mr. Advani, do you want to speak on this? The next statement is yours.

DR. M.N. DAS (Orissa): Mr. Chairman, Sir, I want to say...

MR. CHAIRMAN: There are a number of others also. It is already 1—30 P.M. now.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, shall we meet after lunch?

MR. CHAIRMAN: There is no lunch-break now.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति जी, मैं आभारी हूं श्री गुलाम नबी आजाद का और विभिन्न दलों के सभी प्रतिनिधियों का जो इस विषय पर बोले हैं, उन्होंने जम्मू-कश्मीर की परसों की घटनाओं के संदर्भ में कई बातों को एक साथ व्यक्त किया है, जो उग्रवाद निरीह नागरिकों की जानें ले रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके बारे में वेदना और व्यथा अभिव्यक्त की है। Deep anguish, as Dr. Karan Singh has said. उसके कारण डोडा जिले में आज जो असुरक्षा का वातावरण पैदा हो गया है, उसके बारे में सबने चिंता प्रकट की है। सभी लोगों ने एक स्वर से यह कहा कि पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वॉर को रोकने के लिए और उसमें उसे पराजित करने के लिए, हमारे आपस में चाहे जितने भी राजनीतिक भेद हों, हम सब एक हैं, सदन भी एक है और देश भी एक है। यह भावना अनेक सदस्यों ने प्रकट की कि इस सरकार के आने के बाद भी इस प्रकार की 3 घटनाएं हुई हैं—एक ऊधमपुर में और 2 डोडा में हुई हैं। उसके विषय में सरकार ने जो प्रतिक्रिया प्रकट की कि हम इसके बारे में कार्यवाही कर रहे हैं तो सदस्यों ने पूछा कि क्या वह कार्यवाही फेल हो गई या कार्यवाही हुई नहीं तो इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में आशंकाएं और संदेह प्रकट किए जा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि कुल मिलाकर सभी सदस्यों ने, एक माननीय सदस्य को अपवाद के रूप में छोड़कर जिन्होंने एक प्रकार से पाकिस्तान के इस तर्क को दोहराया जो वह वर्षों से देता रहा है कि हमारे यहां कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं हो रहा है, हम तो वही कर रहे हैं जो कि हिन्दुस्तान हमारे यहां करता है, जो कि सरासर झूठ है, गलत है। यह बात उनको कई बार कही गई है और हमसे जब विदेशी लोग मिलते हैं तो इस विषय में चर्चा करते हैं। वे भी यह मानते हैं कि कराची का दोष भारत पर ठाल देना किसी प्रकार से तथ्य नहीं है। एक अपवाद को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों ने ये चारों बातें कही हैं और मैं इसके लिए सदन को बधाई देता हूं।

महोदय, जो बात आपने कही और श्री प्रणब मुखर्जी ने कही मैं प्रधानमंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो वहां चर्चा चल रही होगी, मैं कह नहीं सकता लेकिन आज की जो बहस हुई है, उसका एक सही संदेश जाएगा विश्व के लिए, देश भर के लिए और मेरे लिए भी और मेरी सरकार के लिए भी।

महोदय, मैं इतना कह सकता हूं कि आज जो जम्मू-कश्मीर की स्थिति है वह लगभग 9 सालों से है। यह समस्या प्रॉक्सी वॉर की उग्र रूप में 1989 से शुरू हुई और 1990 में यह शिखर पर पहुंच गई थी और 1989 से लेकर लगातार इन 9 सालों में कई सालों तक फोकस था कश्मीर की घाटी और कश्मीर की घाटी पर फोकस रखकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी कि वर्षों तक जम्मू-कश्मीर में कोई यात्री नहीं जाते थे, जाने का साहस नहीं करते थे। मैंने 1989 के फिगर्स देखेतो पता लगा कि 1989 में जम्मू-कश्मीर में 5 लाख के करीब लोग गए थे और अभी 2 साल पहले 1996 में देश भर के और विदेशी यात्रियों की कुल संख्या 300 और 400 के बीच थी। यह स्थिति हो गई थी। पहले जब हिंदुस्तान भर के लोग फिल्में बनाते थे तो उन्हें लगता था कि सीनिक ब्यूटी के लिए श्रीनगर चलो, पहलगांव चलो, गुलमर्ग चलो। लेकिन वर्षों से फिल्म वालों ने वहां जाना बंद कर दिया था। इस साल पहली बार स्थिति में परिवर्तन आया और परिणाम यह हुआ है कि वहां पर इस साल हजारों लोग श्रीनगर गये हैं, पहलगांव गए हैं, गुलमर्ग गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह सब इस सरकार ने किया है। स्थिति में परिवर्तन आया है कई कारणों से लेकिन वह स्थिति का परिवर्तन है। कभी-कभी तो यह भी लगता है कि बहुत निराश हो गए हैं मिलिटेंट्स जो घाटी में काम कर रहे थे। हां, उन्होंने अपना ध्यान इस तरफ लगाया है तो हमारा रिस्पांस भी उसी प्रकार से होना चाहिए। उन्होंने डोडा, ऊधमपुर, पुंछ-राजौरी पर कंसनट्रेट किया है और उस कंसनट्रेटेड ऐफर्ट में हम उनको ठीक उत्तर दे सकें, यह जवाबदारी सरकार की जरूर है। और मुझे तो फिगर्स कभी-कभी मिलती है, तो पिछले जुलाई के महीने तक शायद 388 मिलिटेंट जिनमें से 65 फारेन मर्सनरीज थे उनको मारा गया। 545 मिलिटेंट गिरफ्तार हुए हैं। Process of attrition. और इसीलिए मुझे याद है कि मैं कभी-कभी पंजाब जाता था तो लगता था कि स्थिति सुधरेगी नहीं, स्वयं भी निराश होता था। लोग शाम को घर से निकल नहीं सकते थे, शहरों में, गांवों में ऐसी स्थिति थी। लेकिन स्थिति बदली, रामूवालिया जी ने कुछ बातें कहीं, एकाध और सदस्य ने भी बात कही और कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं है, जनता का साथ नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसा कहना उनके साथ अन्याय होगा।

यह स्थिति आज नहीं है। एक फेस था टेरोरिज्म का जब लगता था कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में से, उनका मुकाबला कोई नहीं कर रहा है वहां की पुलिस में। आज वह स्थिति नहीं है और वह स्थिति न होते हुए भी मैं यह नहीं कहूंगा कि ऐसे तत्व नहीं हैं प्रशासन में या पुलिस में कि जिनके बारे में हमको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को या पूरी की पूरी पुलिस को इस प्रकार से और उनको कहना कि वह विश्वास योग्य नहीं है, मैं समझता हूं कि उनके प्रति भी न्याय करना नहीं होगा और वहां की स्थिति को भी संभालने में यह एप्रोच सहायक नहीं होगा। मेरी मान्यता है कि आर्मी, पैरा मिलिट्री फोर्सेज यह अल्टीमेट नहीं हैं सफलता के लिए। पंजाब में भी अगर सफलता मिली तो उसमें प्रमुख भूमिका वहां के प्रशासन की और वहां की पुलिस की थी और उससे भी ज्यादा भूमिका थी वहां की जनता की जिन्होंने उग्रवादियों को सहयोग देना पूरी तरह से बंद कर दिया और मैं मानता हूं कि जम्मू-कश्मीर इस दिशा में बढ़ रहा है। जम्मू काश्मीर में यह सोचना कि हमको कोई जानकारी नहीं मिलती, इंटेलीजेंस नहीं देता, ऐसा नहीं है। हमारे पिछले दिनों में जितनी सारी गिरफ्तारियां वहां पर हुई हैं। जितना कुछ हम कर सके हैं उग्रवादियों के खिलाफ खास करके घाटी के इलाके में तो वह प्रमुख रूप से वहां की जनता से जो हमको जानकारी मिलती रही है उसके आधार पर करते रहे हैं और इसलिए वहां की स्थिति को सही परस्पेक्टिव में पहचान करके, उसके आधार पर उसको डील करना इस सरकार का संकल्प है और मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं और मैंने कभी भी किसी स्टेज पर यह नहीं कहा कि कोई घटना ही नहीं घट सकती। ऐसा संभव नहीं है। मैं अभी-अभी यहां बैठा हूं, तो हमारा मंत्रालय सूचना भेजता है कि गोहाटी में फलाने स्थान पर—नरहरि डिस्ट्रिक्ट, बरामा वहां पर एक बम विस्फोट हुआ है जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। अब यह जो घटनाएं हैं, यह घटनाएं ऐसी हैं कि अधिक से अधिक सावधानी बरतो, अधिक से अधिक काम करो तो भी इन घटनाओं को पूरी तरह से रोक सकना संभव नहीं है। यहां पर इस दिल्ली के शहर में जहां पर किस का राज था, किस का राज नहीं था इसका सवाल नहीं है, लेकिन, दिसम्बर 1996 से लेकर के आज तक 40 बम विस्फोट हुए हैं—दिल्ली और आसपास। मुझे तो इसी बात का समाधान है कि 40 में से 36 के बारे में जो अपराधी थे उन अपराधियों को दिल्ली पुलिस पकड़ पाई, यह बहुत बड़ी बात है। हम अपनी तरफ से इस मामले में देश के सहयोग के साथ, जनता के सहयोग के साथ हम यह संकल्प किए हुए हैं कि हम प्रोक्सी वार में हम देश के दुश्मनों को पराजित करेंगे, हर हालत में पराजित करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्भव है, ऐसा नहीं है कि यह सम्भव नहीं है। योजनाएं कुछ बनाई हैं और आज़मी साहब ने कुछ बातें कहीं, बहुत अच्छी मुझे लगती थी। मैं मन में सोचने लगा कि मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को प्रो-एक्टिव होना चाहिए रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं कि उसकी कितनी आलोचना हुई और प्रो-एक्टिव कहने के बाद किसी ने सवाल पूछा कि इसका मतलब होट परसूट है। मैंने कहा-नहीं है, इसका मतलब हौट परसूट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आज की परिस्थिति में अन्यथा होट परसूट यह परमिटिड है। When we are dealing with an enemey, it is permitted. लेकिन आज की परिस्थिति में हमारी सरकार हौट परसूट की कल्पना नहीं करती क्योंकि उसकी ग्रेविटी हम समझते हैं। लेकिन प्रो-एक्टिव का मतलब यह है कि आपको स्ट्राइक करे मिलिटेंट उसके बाद आप जाकर के उसको पकड़ें, उसके बजाए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज-आपकी जनता का सहयोग उसके आधार पर आप पहले पता लगा करके आप प्रो-एक्टिव होकर के उनके ऊपर एक्शन लें, यह है प्रो-एक्टिव। लेकिन उस एक शब्द को लेकर जैसे मानो पता नहीं क्या अनर्थ कह दिया, कितना कुछ कहा गया। कुल मिला कर देश का माहौल होना चाहिए कि देश का दुश्मन किसी भी रूप में हो और हम पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान की चिंता न करें लेकिन अगर पाकिस्तान प्रॉक्सी वार करने में कुछ भी सफलता पाता है तो उसका कारण थोड़ी बहुत मात्रा में वे इनफिल्ट्रेटर्स हैं जिनको कि रोकना चाहिए सीमा पर, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में जो देश के अलग-अलग भागों में उनको समर्थन देने वाले लोग हैं और उनको समर्थन देने वाले लोगों के बारे में अगर यह सरकार कठोर कार्यवाही करती है तो उस समय जिस प्रकार की आलोचना होती है, उस आलोचना की ही मुझे चिंता है और वह आलोचना नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा का यह तकाज़ा है कि हम देश के दुश्मन खास कर भीतर अगर कोई है तो उसकी पूरी चिंता करें, उसके बारे में किसी भी प्रकार की नरमी न बरतें, यही मेरा निवेदन है।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: घर का भेदी ही लंका ढाता है। बिलकुल सही है, उनको पकड़ना चाहिए।

†مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے ان کو پکڑنا چاہیئے۔

MR. CHAIRMAN: The next item is statement by Shri L.K. Advani on the deportation of certain people from Mumbai by the Maharashtra Government. Seeing the way the debate has gone on now, I hope that Members would put their questions one after another and that they will allow each other to speak and then the hon. Minister will reply.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, in respect of the earlier subject, I would like to inform the House कि उस डोडा की घटना के संदर्भ में आज प्रातः काल हमारे गृह सचिव श्री बी०पी० सिंह, बी०एस०एफ० के डायरेक्टर जनरल श्री राम मोहन और मिलिटरी ऑपरेशन्स के एडीशनल डी०जी० मेजर जनरल सिंह, ये तीनों वहां पर गए हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए और आगे क्या कार्यवाही करनी है, इसको देखने के लिए। तीन कंपनीज़ और उस क्षेत्र में भेज दी गई हैं तुरंत।

MR. CHAIRMAN: Now, the statement by Shri Advani.

STATEMENT BY MINISTER

Deportation of certain people from Mumbai by Government of Maharashtra

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): Sir, various reports have appeared in media regarding the deportation of Bangladeshi nationals from Maharashtra. Maharashtra Government has informed that they had despatched three parties of deportees on 20th, 21st and 22nd July to West Bengal with 24, 34 and 38 deportees respectively.

According to the information furnished by the Government of Maharashtra, an elaborate procedure is followed for detection, identification, and deportation of illegal Bangladeshi immigrants. The suspected foreigners are given adequate opportunity to produce proof of their national status by way of birth certificate, school leaving certificate, ration card, electoral identity card, domicile certificate etc. In the event of failure to produce any such document, the suspect is charged under the relevant provisions of the Passport (Entry into India) Act/ rules and the Foreigners Act, and produced before a metropolitan magistrate who gives sufficient opportunity to such persons for producing proof of nationality. It is only in cases where no such evidence is produced to the satisfaction of the Court that the Court grants permission to the competent authority for deportation of such persons. The competent authority then issues the deportation order under Section 3(2)(c) of the Foreigners Act.

The powers of the Central Government under the Foreigners Act, 1946, Passport (Entry into India) Act, 1920 and the rules and orders framed thereunder have been entrusted to the State Governments/UTs with their prior consent, under Articles 258/239 of the Constitution. These powers *inter alia* include the power to detect and deport the foreign nationals staying illegally.

The procedure for detection and deportation of illegal Bangladeshi immigrants mentioned in para 2 above is being followed by Maharashtra and other States based on which such illegal immigrants are regualrly being deported. Maharashtra Government has further informed that the illegal immigrants who were being taken for deportation thorugh Indo-Bangladesh border in West Bengal were detected to be illegal immigrants in accordance with the above mentioned procedure. It has also been informed that the police parties escorting these deportees were carrying with them deportation order issued by the Deputy Commissioner of Police, Special Branch-I, CID, Mumbai First and third parties of 24 and 38 deportees respectively were handed over to the West Bengal Police at the instance of local district administration. The second party of 34

†[ ]Transilteration in Arabic Script